उत्सर्जन कटौती से भारत के रुख में बदलाव नहीं

नई दिल्ली। विकासशील देशों से भी उत्सर्जन कटौती संबंधी बाध्यकारी शर्तें स्वीकार करने की पर्यावरण एवं वनमंत्री जयराम रमेश की अपील से उलट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज साफ कहा कि फिलहाल इन देशों को उत्सर्जन कटौती के कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य मानने की कोई जरूरत नहीं है और जलवायु परिवर्तन पर भारत के इस रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। डा. सिंह ने ऊर्जा स्रोत संस्थान (टेदी) के तत्वावधान में आज सुबह यहां स्थाई विकास पर 11वें दिल्ली, सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद कहा कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए जो प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं और जो उत्सर्जन कटौती करने में सबसे ज्यादा सक्षम भी हैं, कटौती का भार भी उन्हें ही उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए विकासशील देश बहुत कम जिम्मेदार हैं, दूसरे निरंतर विकास की उनकी बृहत्तर जरूरतों के मद्देनजर इन देशों को स्थाई विकास के लक्ष्य हासिल करने में मदद की जानी चाहिए।

कानूनन रुकावटी लक्ष्य जरूरी नहीं: पीएम

चीन के दावे से अरुणाचल की अखण्डता पर आंच नहीं: प्रधानमंत्री

ईटानगर। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश पर बार-बार दावा करके चीन इस जमीनी हकीकत को नहीं झुठला सकता कि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है। अखिल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ (एएपीएसयू) यहां जारी एक बयान में कहा कि उनके एक प्रतिनिधिमण्डल ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमण्डल को भरोसा दिलाया कि नत्थी वीजा मामले को शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने यह भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश में भी देश का अन्य हिस्सों की तरह विकास एवं समृद्धि की बयार बहेगी।

अरुणाचल भारत का है और रहेगा: सिंह

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा तथा चीनी नक्शों में इस राज्य को उस देश का दिखाए जाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। आल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेण्टस यूनियन (आप्सू) के अध्यक्ष तकाम ततुंग ने कहा कि पीएम ने आप्सू प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान यह बात कही है। ततुंग ने सिंह के हवाले से कहा कि अरुणाचल हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। चीन की ओर से अरुणाचल के लोगों को 'नत्थी वीजा' जारी करने के बारे में सिंह ने कहा कि केन्द्र इस समस्या के जल्द समाधान के लिए जरूरी उपाय कर रहा है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल को अलग-थलग नहीं रखा जा सकता और विकास के फायदे देश के अन्य हिस्सों की तरह उसे भी पहुंचने चाहिए।